अध्याय III

वाणिज्यिक बैंकों का परिचालन और कार्य निष्पादन

प्रस्तावना

3.1 2006-07 के दौरान सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन ने कारोबार और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों[1] के वित्तीय निष्पादन को समर्थन देना जारी रखा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन की महत्वपूर्ण बात लगातार तीसरे वर्ष बैंक ऋण का व्यापक विस्तार था, अलबत्ता इसमें कुछ कमी रही। ऋण वृद्धि की एक महत्वपूर्ण बात लघु क्षेत्र में ऋण का अधिक प्रवाह था। खुदरा क्षेत्र, विशेषतः आवास और वाणिज्यिक स्थावर संपदा, में उल्लेखनीय मंदी आयी। देयता पक्ष में, मुख्य रूप से सावधि जमाओं में तीव्र वृद्धि के कारण जमा वृद्धि में गति आयी । इससे बैंक ऋण की तीव्र मांग का वित्तपोषण आसानी से कर सके। पिछले वर्ष के विपरीत, वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश बढ़े। लेकिन, कुल आस्तियों और निवल मांग तथा मीयादी देयताओं दोनों के प्रतिशत के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश घटते रहे । अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ तेजी से बढ़े, जिसे ऋण की मात्रा में सुदृढ़ वृद्धि और परिचालन व्ययों के नियंत्रण के कारण निवल ब्याज आय में तीव्र वृद्धि से समर्थन मिला। 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ जैसा कि ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में, सकल तथा निवल अनर्जक आस्तियों की गिरावट में परिलक्षित हुआ। बैंकिंग क्षेत्र का जोखिम भारित आस्ति के प्रति पूंजी अनुपात, जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि के बावजूद, पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा।

3.2 इस अध्याय में सकल और बैंक समूह स्तर पर अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन और वित्तीय निष्पादन की रूपरेखा दी गई है। यह अध्याय ग्यारह खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलन पत्र का सकल आधार पर विश्लेषण किया गया है, जबकि खंड 3 में तुलनपत्र से इतर परिचालनों का चित्रण किया गया है। खंड 4 में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण किया गया है। खंड 5 में सुदृढ़ता संकेतकों की प्रवृत्तियों के ब्यौरे दिये गये हैं। खंड 6 में पूंजी बाजार में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालनों के ब्यौरे दिए गए हैं, जबकि खंड 7 में वर्ष के दौरान बैंकिंग में हुई प्रौद्योगिकीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। खंड 8 में बैंकों का क्षेत्रीय विभाजन दिया गया है। खंड 9 में ग्राहक सेवा और वित्तीय समावेशन का अद्यतन स्वरूप दिया गया है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अलावा, 96 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक[2] और चार स्थानीय क्षेत्र बैंक हैं। जबकि इस अध्याय में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निष्पादन मुख्य रूप से दिया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों के निष्पादन का ब्यौरा अलग से क्रमशः खंड 10 और खंड 11 में दिया गया है।

2. अनुसूचित वाणिज्य बैकों की देयताएं और आस्तियां

3.3 निजी क्षेत्र के तीन पुराने बैंकों के विलयन के कारण 2005-06 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की संख्या 85 से घटकर 82 हो गई। 2006-07 के दौरान बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(2) के अनुसार 31 मार्च 2007 को भारत ओवरसीज़ बैंक लि. का इंडियन ओवरसीज़ बैंक में विलय कर दिया गया। बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44क के अंतर्गत दि सांगली बैंक लि. का आइसीआइसीआइ बैंक लि. में 19 अप्रैल 2007 को समामेलन किया गया। गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाड लि. की गिरती वित्तीय दशा को देखते हुए, केंद्र सरकार ने, रिज़र्व बैंक की सिफारिशों पर, बैंक को 7 जनवरी 2006 के कारोबार की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रख दिया। 1 सितंबर 2006 को सरकार द्वारा कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरा करने के बाद, परवर्ती अधिसूचना द्वारा दि गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाद लि. को 2 सितंबर 2006 को फेडरल बैंक लि. के साथ समामेलित किया गया। इसी प्रकार, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 की उप धारा (2) के अंतर्गत यूनाइटिड वेस्टर्न बैंक लि. (यूडब्ल्यूबी) को अधिस्थगन आदेश के अंतर्गत रखा गया। प्रक्रियाएं पूरी होने के पश्चात् यूनाइटिड वेस्टर्न बैंक लि. को 30 सितंबर 2006 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया लि. के साथ समामेलित कर दिया गया। यह समामेलन 3 अक्तूबर 2006 से प्रभावी हुआ। समामेलन की इन घटनाओं के अलावा, दिसंबर 2006 को 75 बैंक परिसमापन के अंतर्गत थे। दो बैंकों के नाम बदल दिए गए हैं अर्थात् यूटीआई बैंक एक्जिस बैंक

[1] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में 28 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (भारतीय स्टेट बैंक तथा 7 इसके सहयोगी बैंक; 19 राष्ट्रीयकृत बैंक और आइडीबीआइ बैंक लि.), 8 नए निजी क्षेत्र के बैंक, 17 पुराने निजी क्षेत्र के बैंक तथा 29 विदेशी बैंक शामिल हैं। गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवाद लिमिटेड, जिसके कार्यों पर 7 जुलाई 2006 को रोक लगाई गई और बाद में जिसका 2 सितंबर 2006 को फेडरल बैंक लिमिटेड में विलय किया गया, ने वर्ष 2005-06 से संबंधित अपने वार्षिक लेखों को प्रकाशित नहीं किया।

[2] मार्च 2007 के अंत के अनुसार

और चोहुंग बैंक शिन्हान बैंक के रुप में होगा। 2006-07 के दौरान तीन समामेलनों के अलावा, सांगली बैंक लि. को 19 अप्रैल 2007 को बैंककारी अधिनियम 1949 की धारा 44 क के अंतर्गत आइसीआइसीआइ बैंक लि. में समामेलित किया गया।

3.4 2005-06 में 18.2 प्रतिशत से तुलना करने पर 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कुल तुलन-पत्र में 24.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई (सारणी III.1और III.2)।

सारणी III.1: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में			
	2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
देयताए				
1. पूंजी	25,206	0.9	29,559	0.9
2. आरक्षित निधियां और अधिशेष	1,57,974	5.7	1,89,615	5.5
3. जमाराशियां	21,64,681	77.7	26,96,980	77.9
3.1. मांग जमाराशियां	2,92,945	10.5	3,51,998	10.2
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	5,42,874	19.5	6,31,651	18.2
3.3. मीयादी जमाराशियां	13,28,861	47.7	17,13,330	49.5
4. उधार राशियां	2,03,147	7.3	2,42,870	7.0
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	2,34,852	8.4	3,04,381	8.8
कुल देयताएं/आस्तियां	**27,85,863**	**100.0**	**34,63,406**	**100.0**
आस्तियां				
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	1,44,475	5.2	1,95,372	5.6
2. बैंकों के पास शेष राशियां और मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	1,16,443	4.2	1,58,413	4.6
3. निवेश	8,66,508	31.1	9,50,769	27.5
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क+ख)	6,90,421	24.8	7,54,456	21.8
क. भारत में	6,86,464	24.6	7,50,733	21.7
ख. विदेश में	3,957	0.1	3,723	0.1
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	13,949	0.5	12,760	0.4
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,62,137	5.8	1,83,551	5.3
4. ऋण और अग्रिम	15,16,811	54.4	19,81,216	57.2
4.1 खरीदे और भुनाए गए बिल	1,03,657	3.7	1,24,424	3.6
4.2 नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट *आदि*	5,65,001	20.3	7,12,866	20.6
4.3 मीयादी ऋण	8,48,152	30.4	11,43,924	33.0
5. अचल आस्तियां	25,081	0.9	31,362	0.9
6. अन्य आस्तियां	1,16,542	4.2	1,46,271	4.2

टिप्पणी : 2005-06 के बैंकों के आंकड़े 2006-07 के बैंकों के तुलनपत्र के अनुसार हैं और चूंकि कुछ बैंकों द्वारा 2005-06 के आंकड़े संशोधित किए गए हैं, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2005-06 में प्रस्तुत आंकड़ों से नहीं मिल सकते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

3.5 वास्तविक अर्थव्यवस्था की तुलना में बैंकिंग प्रणाली के तीव्र विकास से जीडीपी (वर्तमान कीमतों में कारक लागत पर) के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की आस्तियों के अनुपात में काफी वृद्धि हुई, जो मार्च 2006 के अंत के 85.7 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 92.5 हो गई। बैंकिंग प्रणाली में 'लीवरेज' की मात्रा, जैसाकि ईक्विटी गुणज (कुल आस्तियों को कुल ईक्विटी द्वारा विभाजित करके मापा गया) से परिलक्षित होता है, मार्च 2006 के अंत के 15.2 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 15.8 प्रतिशत हो गया ।

3.6 वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की देयताओं और आस्तियों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन हुए। तीसरे वर्ष लगातार, ऋण और अग्रिम 30 प्रतिशत (अर्थात 2005-06 में 31.8 प्रतिशत और 2004-05 में 33.2 प्रतिशत से तुलना करने पर 30.6 प्रतिशत) बढ़े, जिसे सुदृढ़ समष्टि आर्थिक निष्पादन से बल मिला। पिछले दो वर्षों के रुझान को उलटते हुए, जमाओं में समग्र रूप से वृद्धि ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि की तुलना में काफी अधिक थी, यद्यपि 24.6 प्रतिशत की जमा वृद्धि ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि की तुलना में कम थी। अतः गत वर्ष, जब बैंकों ने बढ़ी हुई ऋण की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को बेच दिया, के विपरीत निधियों के अधिशेष के एक हिस्से को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया गया। वृद्धिशील निवेश के बावजूद, कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों (समग्र निवेश भी) का हिस्सा काफी घटा, इसका आशय यह हुआ कि निवेश में वृद्धि की गति समग्र आस्तियों में वृद्धि के समान नहीं है (सारणी III.2 और परिशिष्ट सारणी III.1(क) से (ग)]।

3.7 बैंक समूहों के बीच, विदेशी बैंकों और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के तुलन-पत्र में क्रमशः 39.5 प्रतिशत और 38.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों में उनका संयुक्त हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 22.3 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 24.9 प्रतिशत हो गया (सारणी III.2)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संयुक्त तुलन-पत्र में, संपूर्ण बैंकिंग क्षेत्र के तुलनपत्र में हुई 24.3 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में , 21.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका हिस्सा एक वर्ष पहले के 72.3 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 70.5 प्रतिशत रह गया। ऐसा मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक समूह और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों के हिस्से में गिरावट के कारण था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के तुलन पत्र में 7.1 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि उनका बाजार हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 5.4 प्रतिशत से गिरकर मार्च 2007 के अंत में 4.6 प्रतिशत रह गया [परिशिष्ट सारणी III.1(क) से (ग)]। विभिन्न बैंक समूहों के बाजार हिस्से का परिवर्तन व्यापक रूप से जमाओं में उनके हिस्से में परिवर्तन को परिलक्षित करता है (सारणी III.3)।

सारणी III.2: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र में वृद्धि : बैंक समूह-वार

(प्रतिशत)

मद	मार्च के अंत में									
	2006					2007				
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	निजी क्षेत्र के नए बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. पूंजी	-20.6	25.9	14.2	27.5	-2.7	0.7	4.4	5.6	45.4	17.3
2. आरक्षित निधि और अधिशेष	21.7	19.5	55.2	28.5	27.7	20.0	11.6	17.4	30.6	20.0
3. जमाराशियां	12.9	11.6	50.7	31.7	17.8	22.9	6.0	38.8	32.6	24.6
3.1. मांग जमाराशियां	20.8	15.7	29.3	48.8	24.9	19.3	3.9	36.7	11.8	20.2
3.2. बचत बैंक जमाराशियां	19.0	20.4	60.6	21.1	22.0	15.0	6.7	33.3	16.3	16.4
3.3. मीयादी जमाराशियां	8.9	8.9	53.9	25.4	14.7	27.3	6.1	40.6	52.3	28.9
4. उधार	23.7	22.5	11.0	24.5	20.7	5.7	22.3	42.8	32.7	19.6
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	12.3	13.8	34.0	31.4	17.4	16.2	16.1	51.1	88.7	29.6
कुल देयताएं / आस्तियां	**13.6**	**12.4**	**43.2**	**29.8**	**18.3**	**21.1**	**7.1**	**38.7**	**39.5**	**24.3**
1. भारिबैंक के पास नकदी और शेष राशि	25.3	-0.3	16.1	20.0	22.4	26.1	25.9	94.3	49.8	35.2
2. बैंकों के पास शेष राशियां तथा मांग और अल्पावधि सूचना पर मुद्रा	14.0	7.5	37.4	64.3	22.1	26.9	5.8	91.9	42.2	36.0
3. निवेश	-7.7	1.1	41.1	22.2	-0.4	4.9	-3.6	26.4	36.4	9.7
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क + ख)	-8.4	3.2	50.4	20.1	-1.2	3.6	-2.2	33.0	37.5	9.3
क. भारत में	-8.5	3.2	50.3	20.1	-1.3	3.6	-2.0	32.9	37.5	9.4
ख. विदेश में	15.3	2.6	255.2	–	17.7	-8.6	-100.0	125.0	–	-5.9
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-13.5	-14.4	-60.9	-60.6	-14.4	-7.8	-30.9	-20.7	0.2	-8.5
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	-2.8	-5.8	24.1	32.8	4.8	13.6	-7.6	11.4	32.7	13.2
4. ऋण और अग्रिम	29.5	21.7	50.2	29.5	31.8	30.2	12.0	39.9	29.5	30.6
4.1 खरीद गए तथा भुनाए गए बिल	16.5	8.1	-10.4	27.0	12.8	22.4	-15.4	21.8	21.3	20.0
4.2 नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट आदि	26.9	21.4	64.2	33.7	29.3	25.7	11.6	42.0	27.7	26.2
4.3 मीयादी ऋण	33.5	24.3	54.4	26.6	36.4	34.5	16.5	40.7	32.8	34.9
5. अचल आस्तियां	9.1	7.4	2.5	28.1	8.8	37.7	-5.6	4.2	24.4	25.0
6. अन्य आस्तियां	12.8	14.3	31.3	30.7	18.4	7.1	0.7	33.3	90.6	25.5

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलनपत्र

3.8 पर्यवेक्षण के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में वित्तीय विवरणों की पारदर्शिता की महत्ता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के प्रकटीकरण मानकों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के करीब लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं (बॉक्स III.1)।

सारणी III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के तुलनपत्र के प्रमुख घटक-बैंक समूहवार

(मार्च के अंत में)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	आस्तियाँ		जमाराशियाँ		अग्रिम		निवेश	
	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	72.3	70.5	75.0	73.9	72.9	72.7	73.1	69.9
राष्ट्रीयकृत बैंक	44.3	44.2	48.7	48.8	45.0	45.2	44.3	44.9
स्टेट बैंक समूह	24.8	23.3	25.1	23.5	24.5	24.3	25.9	22.3
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक	3.2	3.0	1.2	1.6	3.5	3.2	2.9	2.7
निजी क्षेत्र के बैंक	20.5	21.5	19.8	20.5	20.6	20.9	20.8	22.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	5.4	4.6	6.0	5.1	5.5	4.7	5.2	4.6
निजी क्षेत्र के नए बैंक	15.1	16.9	13.8	15.3	15.2	16.2	15.6	18.0
विदेशी बैंक	7.2	8.0	5.3	5.6	6.4	6.4	6.0	7.5
अनुसूचित वाणिज्यक बैंक	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

बॉक्स III.1 : बैंकों के तुलन पत्र में प्रकटीकरण और पारदर्शिता

वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण और पारदर्शिता और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि बैंकों के कार्य अधिक जटिल तथा विविधतापूर्ण हो गए हैं। बैंक विशिष्ट हैं। बैंक वित्तीय मध्यस्थ हैं जो बचत जुटाने, निधियों की सुरक्षा और बचतकर्ताओं को अच्छा प्रतिफल देने को ध्यान में रखकर उसे नियोजित करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस प्रकार बैंकों को प्रत्ययी भूमिका और जिम्मेदारी निभानी है। भुगतान प्रणाली के परिचालन के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। बैंकों का निरंतर, स्थिर और सतत परिचालन किसी बैंक और बैंकिंग प्रणाली में जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पूर्ण प्रकटीकरण बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसलिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वार्षिक खातों की पारदर्शिता पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य बाजार सहभागियों द्वारा काफी ध्यान दिया गया है। प्रभावी सार्वजनिक प्रकटीकरण बाजार अनुशासन को बढ़ाता है। बाजार अनुशासन और बेहतर सार्वजनिक संवीक्षा बैंकों को अपना कारोबार सुरक्षित, सुदृढ़ और प्रभावी तरीके से करने; उक्त कारोबार के उद्देश्यों को सुसंगत बनाने; सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रथाओं तथा आंतरिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए प्रबल प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। बाजार अनुशासन, जिसे बेहतर प्रकटीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, को बासेल II के तहत तीन स्तंभों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान करके पर्याप्त महत्व दिया गया है।

1991 से शुरू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के अनुसरण में, रिज़र्व बैंक ने प्रकटीकरण की आवश्यकता, बैंकों की सार्वजनिक जवाबदेही, बैंकर और ग्राहक के बीच गोपनीयता बनाए रखने तथा बैंकों की विश्वसनीयता की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए बैंकों के प्रकाशित खातों में अधिकांश अथवा पूर्ण प्रकटीकरण लाने के लिए कई उपाय किए हैं। निम्नलिखित को ध्यान में रखकर बैंकों के तुलनपत्र और लाभ-हानि खाता के फॉर्मेट में 1991 में संशोधन किए गए (i) अधिकांश अथवा पूर्ण प्रकटीकरण की आवश्यकता (ii) एक अवधि में क्षेत्रवार और सेक्टरवार बैंकिंग परिचालन का विस्तार (iii) खातों के प्रस्तुतीकरण में सुधार की आवश्यकता। संशोधन का मुख्य जोर बैंकों की असली वित्तीय स्थिति को निर्देशित फोकस पर लाने और वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को अध्ययन कर उनकी स्थितियों के बीच सार्थक तुलना करने में समर्थ बनाने पर है। बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे लेखांकन वर्ष के लिए अपने वित्तीय विवरण में 'नोट आन एकॉउंटट के साथ-साथ परिचालनों के प्रमुख क्षेत्र से संबंधित लेखांकन नीतियों को एक स्थान पर प्रकट करें।

संपूर्ण प्रकटीकरण के लिए, वित्तीय विवरण की टिप्पणियों द्वारा कुछ बहुत उपयोगी सूचनाएं अच्छी प्रकार दी जाती है अथवा इस प्रकार ही उन्हें दिया जा सकता है। टिप्पणियों और पूरक जानकारियों का उपयोग कुछ मदों को स्पष्ट और प्रलेखित करने का साधन प्रदान करता है, जो या तो वित्तीय विवरण में दी गई हैं अथवा अन्यथा वे रिपोर्टिंग उद्यम की वित्तीय स्थिति और उसके निष्पादन को प्रभावित करेगी। रिज़र्व बैंक ने बैंकों के लिए निर्धारित प्रकटीकरण अपेक्षाओं में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है। कंप्यूटरीकरण और बैंकों में एमआइएस के स्तर, बाजार के विकास आदि, जैसे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर सहमति है कि पारदर्शिता के स्तर को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के बराबर लाने की आवश्यकता है।उपर्युक्त दृष्टिकोण के अनुसार, बैंकों के प्रकटीकरण मानकों को धीरे-धीरे बढ़ाया गया है। बैंकों के तुलन पत्र में 16 विस्तृत अनुसूचियों के अलावा, उन्हें ञ्नोट टु एकांउटट में ऐसे ब्यौरे देने की आवश्यकता है :

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात; टियर I पूंजी; टियर II पूंजी;
- राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की अंश-धारिता का प्रतिशत;
- टियर II पूंजी के रूप में जुटाए गए गौण ऋण की राशि;
- भारत में और भारत से बाहर निवेश पर पृथक रूप से निवेश का सकल मूल्य और भारत में और भारत से बाहर निवेश का निवल मूल्य;
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत;
- निवेश के मूल्य में ह्रास के लिए किए गए प्रावधान तथा ऐसे प्रावधानों में घट-बढ़;
- निवल अग्रिमों के प्रति निवल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत। अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान और ऐसे प्रावधानों में घट-बढ़;
- पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों के ब्यौरे; सीडीआर के अंतर्गत पुनर्संरचना; आस्ति पुनर्संरचना के लिए एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे; खरीदी/बेची गई अनर्जक आस्ति के ब्यौरे;
- 'प्रावधानों और आकस्मिकताओं' के ब्यौरे; वर्ष के दौरान आयकर, मानक आस्ति, अस्थायी प्रावधान आदि, के लिए किए गए प्रावधान;
- कारोबार अनुपात जैसे कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय; कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ; आस्तियों पर प्रतिफल, प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा और अग्रिम) और प्रति कर्मचारी लाभ का प्रकटीकरण;
- आस्ति-देयता प्रबंधन - ऋणों और अग्रिमों के परिपक्वता का स्वरूप; निवेश प्रतिभूतियां; जमा राशियां; उधार; और विदेशी मुद्रा आस्ति और देयताएं;
- संवेदनशील क्षेत्र को उधार, जो आस्ति मूल्य उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील है। इसमें ऐसे क्षेत्रों जैसे पूँजी बाजार, जमीन जायदाद आदि, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा संवेदनशील परिभाषित किए जाते हैं, को दिए गए अग्रिम शामिल हैं;
- देश जोखिम के प्रति एक्सपोजर;
- बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता की सीमा को पार करने के ब्यौरे
- रेपो लेन-देन; गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलिया; वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप; एक्सचेंज में ट्रेडिंग किये जाने वाले ब्याज दर व्युत्पन्नी; और व्युत्पन्नियों में जोखिम एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण।

बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विभिन्न लेखांकन मानकों के अंतर्गत दिए गए प्रकटीकरण मानकों का अनुपालन करना है।

जमाराशियां

3.9 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल जमाराशियों में पिछले वर्ष के 17.8 प्रतिशत की तुलना में 24.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि मांग जमाओं और बचत बैंक जमाराशियों की वृद्धि घटी, मीयादी जमाराशियों की वृद्धि में तेजी आयी। यह पिछले वर्ष के रुझान के विपरीत था, जब ऋण की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जमाराशियां बढ़ाने के बैंकों के प्रयासों से जमाओं के परिपक्वता स्वरूप को काफी छोटा करना पड़ा, जो मांग और बचत बैंक जमाओं की तीव्र वृद्धि में परिलक्षित हुआ। 2006-07 में कई कारकों ने मीयादी जमाराशियों की तीव्र वृद्धि में योगदान दिया। प्रथम, अनुकूल ब्याज दर अंतर और लघु बचतों एवं इक्विटी संबद्ध निवेशों को मिलने वाले कर लाभ को दीर्घावधि बैंक जमाओं को भी उपलब्ध कराने के कारण डाक बचतों से बैंकों की मीयादी जमाओं की ओर स्पष्ट अंतरण हुआ। दूसरे, नकदी संपन्न निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से भी मीयादी जमाओं की मांग बढ़ी, जिन्होंने अधिक लाभप्रदता के कारण अपनी अतिरिक्त निधियों को बैंकों में जमा किया। तीसरे, 2006-07 के दौरान पिछले वर्ष से तुलना करने पर अनिवासी जमाओं में तेज वृद्धि हुई।

3.10 हाल के वर्षों में जमा प्रमाण पत्रों के निर्गम में दिखी तेज वृद्धि 2006-07 के दौरान जारी रही। बकाया जमा प्रमाणपत्रों की राशि मार्च 2006 के अंत के 43,568 करोड़ रुपए से दुगुने से अधिक बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 93,272 करोड़ रुपए और 28 सितंबर 2007 को 1,18,481 करोड़ रुपए हो गई। बकाया जमा प्रमाणपत्र एक वर्ष पहले के 1.6 प्रतिशत से तुलना करने पर मार्च 2007 के अंत में अनुसूचित वाणिज्य बैंक की कुल जमाओं का 2.7 प्रतिशत थे। 2006-07 के दौरान जमा प्रमाण पत्रों के बढ़े हुए निर्गम ने सुदृढ ऋण उठाव को देखते हुए जमाराशियां जुटाने में बैंकों के समक्ष उपस्थित दवाबों को परिलक्षित किया। भारी जमाराशियां आकर्षित करने के लिए नकदी का संकट झेल रहे बैंकों द्वारा प्रस्तावित प्रतिलाभ के लोच ने संसाधन जुटाने के लिए जमा प्रमाण पत्रों को पसंदीदा मार्ग बनाया। निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक, जिनका शाखा नेटवर्क और फुटकर ग्राहक आधार सीमित है, जमा प्रमाण पत्रों के बड़े निर्गमकर्ता बने रहे (परिशिष्ट सारणी III.2)।

3.11 बैंक समूहवार, निजी क्षेत्र के नए बैंकों की जमाराशियां सर्वाधिक दर (38.8 प्रतिशत) से बढ़ीं, इसके पश्चात् विदेशी बैंकों (32.6 प्रतिशत), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (22.9 प्रतिशत) और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों (6.0 प्रतिशत) का स्थान था। पिछले कुछ वर्षों के रुझान को जारी रखते हुए, वर्ष के दौरान कुल जमाओं में निजी क्षेत्र के नए बैंकों का हिस्सा और बढ़ा, जबकि

चार्ट III.1: कुल जमाराशियों में अंश - बैंक समूहवार
(मार्च के अंत में)

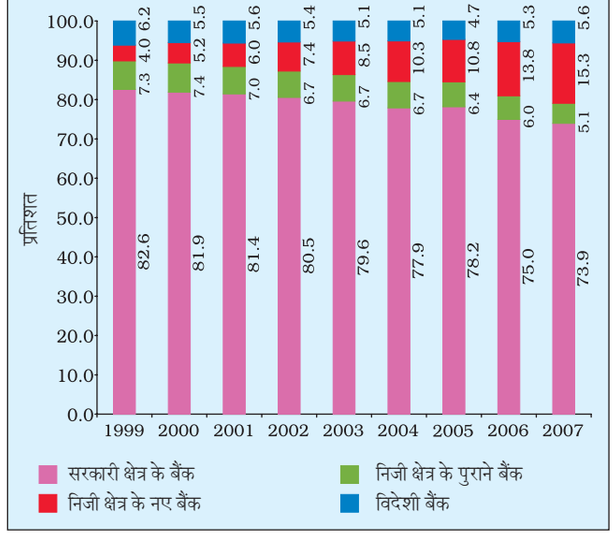

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों का हिस्सा कम हुआ (चार्ट III.1)।

गैर-जमा संसाधन

3.12 ईक्विटी और ऋण के सार्वजनिक निर्गम के रूप में बैंकों द्वारा पूँजी बाजार से जुटाए गए संसाधन 2005-06 के 11,067 करोड़ रुपए से तेजी से घटकर 2006-07 के दौरान 1,066 करोड़ रुपए रह गए। लेकिन, बैंकों ने निजी प्लेसमेंट बाजार से बड़ी-बड़ी निधियां (पिछले वर्ष के 97 निर्गमों से 30,151 करोड़ रुपए की तुलना में 90 निर्गमों से 30,994 करोड़ रुपए) जुटाना जारी रखा (ब्यौरे के लिए खंड 6 देखें)।

बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं

3.13 बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताओं में 2005-06 में हुई 20.2 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2006-07 के दौरान 17.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अंतरराष्ट्रीय देयताओं की वृद्धि में कमी, मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा उधारों में गिरावट और एनआरई जमाओं में कम वृद्धि के कारण थी। तथापि, एफसीएनआर(बी) जमाराशियां, एनआरओ रुपया जमाराशियां, प्रतिभूतियों के अपने निर्गम और अन्य देयताएं, जो मुख्य रूप से एडीआर, जीडीआर के माध्यम से जुटाए गए आगमों तथा अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की ईक्विटी के कारण थीं, तेज गति से बढ़ीं (सारणी III.4)।

3.14 पिछले कुछ वर्षों की प्रवृत्ति को पलटते हुए कुल अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमा और उधार के हिस्से में वर्ष के दौरान कमी आयी। (चार्ट III.2)

सारणी III.4: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय देयताएं – प्रकार

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च के अंत में		
	2005	2006	2007
1	2	3	4
1. जमाराशियां और ऋण	**2,03,154**	**2,46,246**	**2,71,403**
	(79.7)	**(80.3)**	**(75.2)**
जिनमें से:			
क) विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक[एफसीएनआर(बी)]	50,796	58,110	68,086
	(19.9)	(19.0)	(18.9)
ख) विदेशी मुद्रा उधार*	45,539	63,722	61,470
	(17.9)	(20.8)	(17.0)
ग) अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरइ) खाता	85,811	1,00,310	1,12,907
	(33.7)	(32.7)	(31.3)
घ) अनिवासी सामान्य (एनआरओ) रुपया जमाराशियां	6,393	5,449	6,855
	(2.5)	(1.8)	(1.9)
2. प्रतिभूति /बांडों (आइएमडी/आर आइबी सहित) के अपने निर्गम	**29,235**	**4,856**	**10,036**
	(11.5)	**(1.6)**	**(2.8)**
3. अन्य देयताएं	**22,609**	**55,506**	**79,258**
	(8.9)	**(18.1)**	**(22.0)**
जिनमें से:			
क) एडीआर/जीडीआर	9,910	14,835	23,515
	(3.9)	(4.8)	(6.5)
ख) अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	3,230	28,438	40,328
	(1.3)	(9.3)	(11.2)
ग) भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/विप्रेषणीय लाभ और अन्य अवर्गीकृत अन्तरराष्ट्रीय देयताएँ	9,469	12,233	15,415
	(3.7)	(4.0)	(4.3)
कुल अंतरराष्ट्रीय देयताएं	**2,54,999**	**3,06,609**	**3,60,698**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**

* : भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार, बैंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार।
टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल का प्रतिशत हैं ।
स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकी।

3.15 कुल देयताओं में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की निधियों के बाह्य (अंतरराष्ट्रीय) स्रोतों के हिस्से में, जिसमें मार्च 2001 के अंत और मार्च 2006 के अंत के बीच लगभग लगातार वृद्धि हुई, वर्ष के दौरान कमी आई (चार्ट III.3)।

चार्ट III.2: अंतरराष्ट्रीय देयताओं में विदेशी मुद्रा जमा और उधार
(मार्च के अंत में)

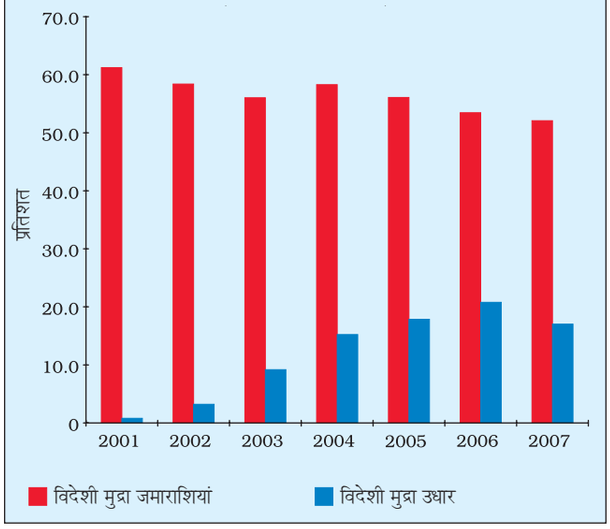

चार्ट III.3: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल देयताओं की तुलना में विदेशी मुद्रा देयताएं
(मार्च के अंत में)

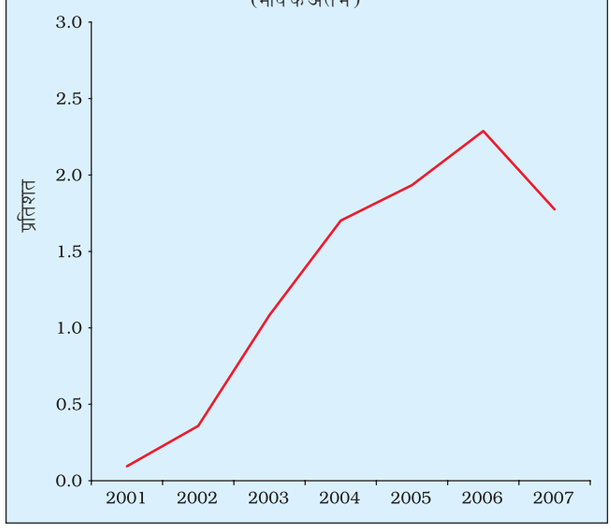

बैंक ऋण

3.16 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के ऋणों और अग्रिमों में 2005-06 के 31.8 प्रतिशत और 2004-05 के 33.2 प्रतिशत की अधिक वृद्धि से ऊपर 2006-07 के दौरान 30.6 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई । बैंक ऋण के बड़े घटकों के बीच, मीयादी ऋण, जो ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो का बड़ा घटक था, का वर्ष के दौरान तेज गति (34.9 प्रतिशत) से बढ़ना जारी रहा। परिणाम के रूप में, वर्ष के दौरान कुल अग्रिमों और सकल घरेलू पूँजी निर्माण (जीडीसीएफ) दोनों में मीयादी ऋण का हिस्सा और बढ़ा (चार्ट III.4)। ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो के अन्य घटक अर्थात नकद ऋण तथा ओवरड्राफ्ट और खरीदे गए तथा बट्टा किए गए बिल समग्र बैंक ऋण की वृद्धि की तुलना में कम दर पर बढ़े।

बैंक ऋण का क्षेत्रीय नियोजन

3.17 समग्र ऋण[3] में मामूली कमी सभी चार बड़े क्षेत्रों अर्थात, कृषि, उद्योग सेवा तथा वैयक्तिक ऋणों सेवाओं में दिखी। सेवाओं (विशेष रूप से वास्तविक जमीन जायदाद ऋणों में) और वैयक्तिक ऋणों में काफी गिरावट हुई है। तथापि, लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए ऋण में तेजी से वृद्धि हुई (सारणी III.5 और परिशिष्ट सारणी III.3)।

3.18 17 अगस्त 2007 तक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन के अनंतिम आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष दर वर्ष आधार पर कृषि, उद्योग, सेवा तथा वैयक्तिक ऋणों के लिए बैंक ऋण घटकर क्रमशः 24.4 प्रतिशत, 24.6 प्रतिशत, 24.5 प्रतिशत और 19.8 प्रतिशत रह गए। जमीन-जायदाद के ऋणों की वृद्धि, 52.9 प्रतिशत की थोड़ी गिरावट के बावजूद, अधिक बनी रही।

चार्ट III.4: मीयादी ऋण और पूंजी निर्माण

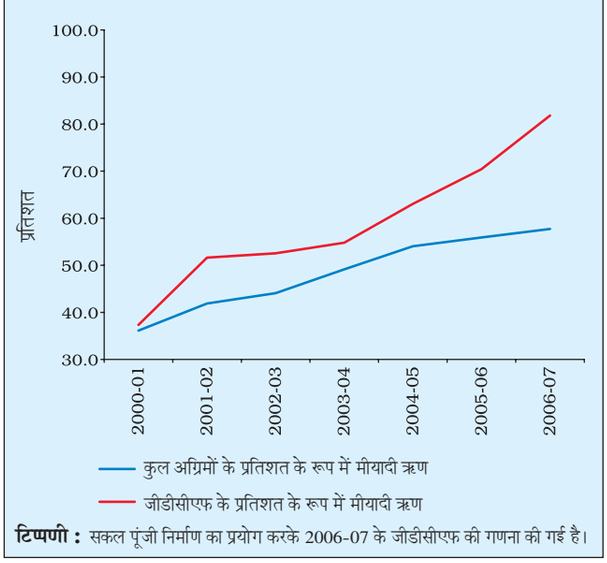

टिप्पणी : सकल पूंजी निर्माण का प्रयोग करके 2006-07 के जीडीसीएफ की गणना की गई है।

सारणी III.5: खाद्येतर ऋण का क्षेत्रवार नियोजन - प्रवाह
(वर्ष में घट-बढ़)

(राशि करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2005-06		2006-07	
	समग्र	प्रतिशत	समग्र	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप	**49,606**	**39.9**	**56,305**	**32.4**
2. उद्योग (लघु, मध्यम और बड़े)	**1,26,804**	**30.0**	**1,41,543**	**25.7**
जिसमें से : लघु उद्योग	16,831	22.7	25,888	28.4
3. वैयक्तिक ऋण	**1,03,733**	**40.5**	**95,422**	**26.5**
जिसमें से : आवास	51,273	38.3	45,508	24.6
4. अन्य सेवाएं	**1,18,254**	**58.8**	**98,857**	**31.0**
जिनमें से:				
i) थोक व्यापार	8,025	25.4	9,922	25.1
ii) स्थावर संपदा	13,147	97.1	18,635	69.8
iii) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	11,463	50.3	14,226	41.5
कुल खाद्येतर सकल बैंक ऋण (1 से 4)	**3,98,396**	**39.6**	**3,92,128**	**27.9**
जिनमें से : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,35,222	36.1	1,22,472	24.0

टिप्पणी 1. आंकड़े अनंतिम हैं और चयनित अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के बैंक ऋण के 90 प्रतिशत से अधिक हैं।
2. क्षेत्रों के पुनर्वर्गीकरण एवं बैंकों के कार्यक्षेत्र विस्तार के कारण 2004-05 (47 बैंकों) के आंकड़े 2005-06 (52 बैंकों) से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं ।
3. 2005-06 के घट-बढ़ में (वर्षभर में 26 पखवाड़ों के बजाय) 27 पखवाड़ो के आंकड़े शामिल हैं ।
4. सकल बैंक ऋण के आंकड़ों में रिज़र्व बैंक, एक्जिम बैंक, अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं और अंतर बैंक सहभागिता के साथ पुनः भुनाए गए बिल शामिल है ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम

3.19 प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार देने में बैंकों का निष्पादन हाल के वर्षों में सुधरा है, यद्यपि विभिन्न बैंक समूहों के निष्पादन में और साथ ही प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत उपलक्ष्यों को पूरा करने में काफी घटबढ़ देखा गया है (बॉक्स III.2)।

3.20 सार्वजनिक और निजी बैंकों के अंतर्गत अलग-अलग बैंकों के स्तर पर, केवल पांच बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समग्र लक्ष्य और कृषि तथा कमजोर वर्ग को उधार देने के उप-लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इकतीस बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक और

[3] अनुसूचित वाणिज्य बैंकों क्षेत्रीय ऋण आंकड़ों के अनुसार

बॉक्स III.2: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने में बैंकों का निष्पादन

देश के व्यापक हित में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के रूप में ज्ञात अर्थव्यवस्था के कतिपय क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को माध्यम प्रधान करने की आवश्यकता के स्पष्टीकरण को वर्ष 1967-68 के लिए रिज़र्व बैंक की ऋण नीति में देखा जा सकता है। कृषि उत्पादन में कमी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में अर्थव्यवस्था में भारी असंतुलन उत्पन्न हुए हैं। भारत सरकार ने आर्थिक आयोजना तथा कृषि और लघु उद्योगों (एसएसआइ) की सहायता के लिए एक अधिक सक्रिय और सकारात्मक भूमिका अदा करने हेतु आर्थिक आयोजना की आवश्यकताओं के लिए एक बेहतर बैंकिंग प्रणाली शुरू करने की दृष्टि से वर्ष 1967-68 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण के लिए उपाय शुरू किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक उद्देश्य था कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ता के बड़े अथवा छोटे होने पर ध्यान दिए बिना ऋण सहायता में कमी का कोई व्यवहार्य उत्पादक प्रयास न हो। इसप्रकार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार की अवधारणा का आगे विकास इसलिए हुआ कि बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को और राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुसार वृद्धिशील तरीके से सहायता जारी रखने को सुनिश्चित किया जा सके।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विवरण को रिज़र्व बैंक द्वारा गठित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम से संबंधित साख्यिकी पर औपचारिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1972 में औपचारिक स्वरूप दिया गया। यद्यपि प्रारंभ में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए उधार के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे, नवंबर 1974 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सूचित किया गया कि मार्च 1979 तक उनके प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए दिए गए उधार बकाया ऋण के एक तिहाई स्तर तक नहीं पहुँचने चाहिए। नवंबर 1978 में निजी क्षेत्रों के बैंकों भी सूचित किया गया कि वे मार्च 1980 के अंत तक के अपने कुल अग्रिमों का न्यूनतम 33 1/3 प्रतिशत उधार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दें। उसके बाद इस लक्ष्य को बढ़ाकर सकल अग्रिमों का 40 प्रतिशत किया गया। इस समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने में बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र और कमजोर वर्गों के लिए उधार के उप-लक्ष्य भी निर्धारित किए गए। वर्तमान बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का क्रमशः न्यूनतम 18 प्रतिशत और 10 प्रतिशत कृषि क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों को उधार प्रदान करें।

भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों भी सूचित किया गया था कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए अपने अग्रिमों को निरंतर बढ़ाते हुए मार्च 1992 के अंत तक अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के 15 प्रतिशत का स्तर प्राप्त करें। अप्रैल 1993 में यह अनुपात और बढ़कर निवल बैंक ऋण का 32 प्रतिशत हो गया जिसे मार्च 1994 तक प्राप्त किया जाना था। 32 प्रतिशत के वर्धित लक्ष्य के भीतर लघु उद्योग के संबंध में उप-लक्ष्य 10 प्रतिशत और निर्यात के संबंध में 12 प्रतिशत निर्धारित किए गए थे। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने संबंधी संशोधित दिशा-निर्देशों के आधार पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्यों/उपलक्ष्यों को अब 30 अप्रैल 2007 से समायोजित निवल बैंक ऋण अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर के ऋण के बराबर राशि, जो भी अधिक हो, से जोड़ा गया हैं।

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण में वृद्धि, पिछले वर्ष के 36.1 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 24.0 प्रतिशत हो गई। 2006-07 के दौरान 'अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र' को दिए गए ऋण, जिनमें हाल के वर्षों में तीव्र वृद्धि दिखी, भी तीव्रता से घटे । तथापि, जहाँ कृषि को ऋण वृद्धि में कमी आयी, वहीं लघु उद्योग को ऋण वृद्धि में तेजी आयी (सारणी 1)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 5,21,180 करोड़ रुपए थे।

सारणी 1: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ग	को बकाया			
	19, मार्च 2004	18, मार्च 2005	31, मार्च 2006	30, मार्च 2007
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (क+ख+ग)	**2,63,834 (24.7)**	**3,74,953 (42.1)**	**5,10,175 (36.1)**	**6,32,647 (24.0)**
क) कृषि	90,541 (23.2)	1,24,269 (37.3)	1,73,875 (39.9)	2,30,180 (32.4)
ख) लघु उद्योग	65,855 (9.0)	74,189 (12.7)	91,020 (22.7)	1,16,908 (28.4)
ग) अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,07,438 (38.3)	1,76,495 (64.3)	2,45,280 (39.0)	2,85,559 (16.4)

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर के है जो प्रतिशत में दिए गए हैं।
2. क्षेत्र के पुनः वर्गीकरण और बैंक के कवरेज में वृद्धि के कारण 2004-05 (47 बैंक) के आंकड़े बाद के बरसों में पूरी तरह से तुलनीय नहीं है ।
3. आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण इस सारणी में दिए गए आंकड़े सारणी 2 और सारणी 3 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम, जो 2005-06 के 33.4 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के दौरान 27.2 प्रतिशत बढ़े, 40 प्रतिशत के लक्ष्य के विपरीत निवल बैंक ऋण का 39.6 प्रतिशत थे । मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को कृषि को दिए गए अग्रिम निवल बैंक ऋण का 15.6 प्रतिशत थे (सारणी III.2 तथा परिशिष्ट सारणी III.5)। एक समूह के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मार्च 1999 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। लक्ष्य पहली बार 2000 में प्राप्त किया गया और एक समूह के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2005-06 तक लक्ष्य को पूरा करना जारी रखा। लेकिन, एक समूह के रूप में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार में, मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को, 40 प्रतिशत के लक्ष्य से 0.4 प्रतिशत की मामूली गिरावट हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के सात बैंक (इलाहाबाद बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स, सिंडीकेट बैंक, आइडीबीआइ लि., भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के 40 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए (परिशिष्ट सारणी III.5 और 5क)। सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों में से केवल आठ बैंक (इलाहाबाद, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र) कृषि को उधार देने के 18 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। कमजोर वर्गों को उधार देने के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के केवल सात बैंकों ने (बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 10 प्रतिशत के उपलक्ष्य को प्राप्त किया।

निजी क्षेत्र के बैंक

मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम 1,43,768 करोड़ रुपए थे, जो निवल

सारणी 2: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के बैंक	
	2006	2007@	2006	2007@
1	2	3	4	5
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	**4,09,748 (40.3)**	**5,21,180 (39.6)**	**1,06,586 (42.8)**	**1,43,768 (42.7)**
जिसमें से:				
कृषि	1,55,220 (15.3)	2,05,091 (15.6)	36,712 (13.6)	52,056 (12.8)
लघु उद्योग	82,434 (8.1)	1,04,703 (8.0)	10,421 (4.2)	13,063 (3.9)
अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	1,63,756 (16.1)	2,01,023 (15.3)	57,777 (23.2)	76,925 (22.9)

@: अनंतिम

टिप्पणी: 1. कोष्ठक के आंकड़े संबंधित समूह के लिए निवल बैंक ऋण के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

2. कृषि के प्रतिशत के आकलन के लिए अप्रत्यक्ष कृषि को निवल बैंक ऋण के 4.5 प्रतिशत तक गिना जाता है।

3. आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण इस सारणी में दिए गए आंकड़े सारणी 1 और सारणी 3 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है।

बैंक ऋण का 42.7 प्रतिशत थे (सारणी 2 और परिशिष्ट सारणी III.7 और 7क)।एक समूह के रूप में, निजी क्षेत्र के बैंक 2001-02 तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 40 प्रतिशत उधार देने के समग्र लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। यह लक्ष्य पहली बार 2002-03 में प्राप्त किया गया। निजी क्षेत्र के 26 बैंकों में से चार बैंक (बैंक ऑफ राजस्थान लि.,सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लि., आइसीआइसीआइ बैंक लि., जम्मू और कश्मीर बैंक लि. तथा कर्नाटक बैंक लि.) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए (परिशिष्ट सारणी III.7 और 7क) । निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए उधार मार्च 2000 के अंत में निवल बैंक ऋण के 8.3 प्रतिशत से सुधरकर मार्च 2006 के अंत में 13.6 प्रतिशत हो गया तथा वह गिरकर मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को निवल बैंक ऋण का 12.8 प्रतिशत रह गया। केवल तीन बैंक (यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक और सांगली बैंक) मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को कृषि के 18 प्रतिशत के उप लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अन्य छह बैंकों द्वारा दिए गए उधार 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के बीच थे। कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले 10 प्रतिशत के लक्ष्य को निजी क्षेत्र का कोई बैंक प्राप्त नहीं कर सका।

विदेशी बैंक

भारत में कार्यालय रखने वाले विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए बकाया अग्रिम मार्च 2003 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के 14,555 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को 37,835 करोड़ रुपए हो गये, जो शुद्ध बैंक ऋण का 33.4 प्रतिशत है (सारणी 3 तथा परिशिष्ट सारणी III.8)। कुल निवल बैंक ऋण में निर्यात ऋण का 18.3 प्रतिशत का हिस्सा 12.0 प्रतिशत के निर्धारित उपलक्ष्य से काफी ऊपर था। विदेशी बैंक भी लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के 10.0 प्रतिशत के उपलक्ष्य पर पहुँच गए (सारणी III.8)। समूह के रूप में, विदेशी बैंक 1997 से निवल बैंक समूह के 32 प्रतिशत के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के समग्र लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को, भारत में कार्यरत 29 विदेशी बैंकों में से पाँच बैंक (आबूधावी कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो - मित्सुबिशी, सिटी बैंक, एचएसबीसी लि. तथा मिजूहो कारपोरेट बैंक) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के निवल बैंक ऋण के 32 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। सात विदेशी बैंक (बैंक ऑफ नोवा स्कोशिया, बैंक ऑफ टोक्यो - मित्सुबिशी, सिटी बैंक, एचएसबीसी लि., जेपी मोर्गन चेज बैंक, मिजूहो कॉरपोरेट बैंक और शिन्हन बैंक) मार्च 2007 के अंत में लघु उद्योग क्षेत्र को उधार देने के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जबकि तीन विदेशी बैंक (अमरीकन एक्सप्रेस बैंक, बैंक इंटरनेशनल इंडोनेशिया और मिजूहो कॉरपोरेट बैंक) निर्यात के लिए उधार देने के उपलक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके (परिशिष्ट सारणी III.8क)।

कृषि में कम पूँजी निर्माण के कारण सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कई बैंक कृषि उधार लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, जिसका परिणाम कमजोर ऋण अवशोषण और अनर्जक ऋणों को बट्टे में डालना रहा, जिससे कुछ बैंकों के बकाया अग्रिम घटे।

सारणी 3: विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार

(मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2005		2006		2007@	
	राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत	राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत	राशि	निवल बैंक ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम #	**23,843**	**35.3**	**30,439**	**34.4**	**37,835**	**33.4**
जिसमें से:						
निर्यात ऋण	12,339	18.3	17,326	19.6	20,714	18.3
लघु उद्योग	6,907	10.2	8,430	9.5	11,648	10.3

@ : अनंतिम।

: औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के ऋण, सॉफ्टवेयर उद्योग, खाद्य और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र, स्वयं सहायता समूह और उद्यम पूंजी को दिए गए ऋण शामिल हैं।

टिप्पणी : आंकड़ों के विभिन्न स्रोतों के कारण इस सारणी में दिए गए आंकड़े सारणी 1 और सारणी 2 के आंकड़ों से मेल नहीं खाते है।

निजी क्षेत्र के 19 बैंक) समग्र लक्ष्य को प्राप्त कर सके, लेकिन उप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। दस बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के छह बैंक और निजी क्षेत्र के चार बैंक) समग्र लक्ष्य और उप-लक्ष्य को भी प्राप्त नहीं कर पाए (सारणी III.6, परिशिष्ट सारणी III.5क और परिशिष्ट सारणी III 7 क)।

विशेष कृषि ऋण योजना

3.21 रिज़र्व बैंक ने कृषि के लिए ऋण प्रवाह में सुस्पष्ट और निर्दिष्ट सुधार की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि वे 1994-95 से वार्षिक आधार पर विशेष कृषि ऋण योजनाएं (एसएसीपी) बनाएं। विशेष कृषि ऋण योजना के अन्तर्गत बैंकों से वर्ष के दौरान (अप्रैल-मार्च) अपेक्षा है कि वे प्राप्त करने के लिए अपने लिए लक्ष्य बनाएं। बैंक सामान्यतया पिछले वर्ष किए गए संवितरण से लगभग 20-25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हाल के वर्षों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने व्यापक रूप से विशेष कृषि ऋण योजना के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। 2006-07 के वित्तीय वर्ष के लिए योजना के अन्तर्गत कृषि के लिए संवितरण, 1,18,160 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत, कुल 1,22,443 करोड़ रुपए था, जो लक्ष्य का 103.6 प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 से निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी विशेष कृषि ऋण योजना व्यवस्था लागू की गई। 2005-06 के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए संवितरण, 24,222 करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 31,199 करोड़ रुपए था। 2006-07 के दौरान, निजी क्षेत्र के बैंकों ने, 40,656 करोड़ रुपए के अपने निर्धारित लक्ष्य की तुलना में योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र के लिए 35,585 करोड़ रुपए संवितरित किए।

3.22 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई कि वे अपने निवल बैंक ऋण का 5 प्रतिशत महिलाओं के लिए निर्धारित करें। मार्च 2007 के अंत में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिया गया कुल ऋण उनके निवल बैंक ऋण का 4.95 प्रतिशत था जिसमें 21 बैंक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके।सार्वजनिक क्षेत्र के आठ बैंकों ने 15 विशेष महिला शाखाएं खोली हैं।

सारणी III.6: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति

(बैंकों की संख्या)

	क्रम लक्ष्य / उप-लक्ष्य स	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
	1	2	3	4
1.	कुल / कृषि / कमजोर वर्ग	5	–	5
2.	केवल कुल	12	19	31
3.	कुल और कृषि	2	3	5
4.	कुल और कमजोर वर्ग	1	–	1
5.	कृषि और कमजोर वर्ग	–	–	–
6.	केवल कृषि	1	–	1
7.	केवल कमजोर वर्ग	1	–	1
8.	कोई नहीं	6	4	10

– : कुछ नहीं

सूक्ष्म-वित्त

3.23 स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्ध कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्म-वित्त कार्यक्रम के रूप में उभरा है। इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्च 2007 के अंत में, सामूहिक रूप से 2.9 मिलियन स्वयं सहायता समूह बैंकों से संबंद्ध थे और इन स्वयं सहायता समूहों को दिया गया कुल ऋण का प्रवाह 18,041 करोड़ रुपए से अधिक था। वर्ष के दौरान दिया गया कुल बैंक ऋण 6,643 करोड़ रुपए था जिसमें स्वयं सहायता समूहों को दोबारा दिए गए ऋण की राशि 3,599 करोड़ रुपए थी। बैंकों ने 2006-07 के दौरान 686,408 नए स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिए (ब्यौरे के लिए अध्याय IVदेखें)।

उद्योग को ऋण

3.24 उद्योगों (लघु, मध्यम और बड़े) को दिए गए ऋण में वृद्धि पिछले वर्ष के 30.0 प्रतिशत से घटकर 2006-07 में 25.7 प्रतिशत रह गई । चूंकि उद्योग को दिए गए ऋण में हुई वृद्धि समग्र ऋण वृद्धि के समान नहीं रही, खाद्येतर सकल बैंक ऋण में उद्योग के बकाया ऋण का हिस्सा मार्च 2006 के अंत के 39.2 प्रतिशत और मार्च 2005 के अंत के 42.1 प्रतिशत से घटकर मार्च 2007 के अंत में 38.5 प्रतिशत रह गया। वृद्धिशील बैंक ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा (21.4 प्रतिशत) आधारभूत सुविधा उद्योग के लिए था, इसके पश्चात् वस्त्र (14.1 प्रतिशत) और मूल धातु तथा धातु उत्पाद (12.4 प्रतिशत) थे (परिशिष्ट सारणी III.9)। पावर (आधारभूत सुविधा के अन्तर्गत) और लोहा तथा इस्पात (धातु और धातु उत्पाद उद्योग के अन्तर्गत) में सर्वाधिक वृद्धि हुई। अन्य बड़े उद्योग, जिनमें बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ा, पेट्रोलियम, खाद्य प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग, रसायन और निर्माण थे (चार्ट III.5)।

लघु उद्योग क्षेत्र को ऋण

3.25 मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण 1,04,703 करोड़ रुपए थे, जो निवल बैंक ऋण का 8.0 प्रतिशत और इन बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिमों का 20.1 प्रतिशत था। लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, कुटीर उद्योग, कारीगर और छोटे उद्योगों को दिए गए अग्रिम 44,311 करोड़ रुपए थे, जो लघु उद्योग क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का 42.3 प्रतिशत था। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 13,063 करोड़ रुपए था, जो निवल बैंक ऋण का 3.9 प्रतिशत और इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

चार्ट III.5: सकल बैंक ऋण का उद्योगवार नियोजन

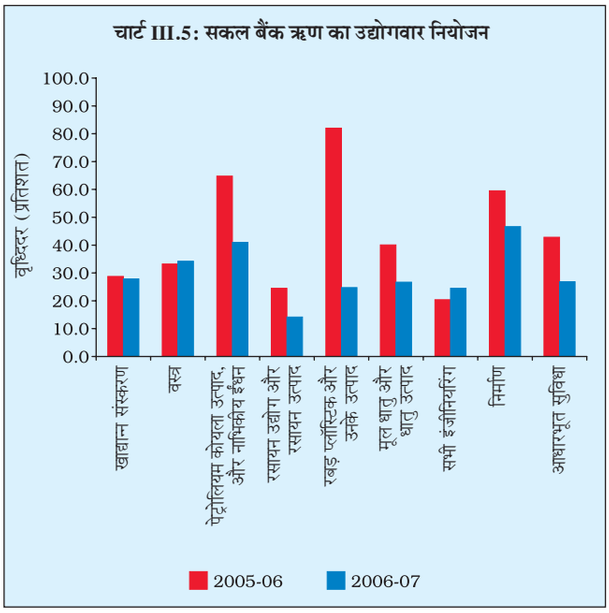

को दिए गए कुल अग्रिमों का 9.1 प्रतिशत था। मार्च 2007 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार को विदेशी बैंकों द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को दिया गया कुल ऋण 11,648 करोड़ रुपए था जो निवल बैंक ऋण का 10.3 प्रतिशत और इन बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों का 30.8 प्रतिशत था।

3.26 मार्च 2007 के अंत में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा 1,14,132 बीमार लघु उद्योग इकाइयों को दिया गया ऋण 5,267 करोड़ रुपए था। बीमार लघु उद्योग इकाइयों में, 4,287 इकाइयां, जिन पर 427 करोड़ रुपए बैंक ऋण बकाया था, अर्थक्षम पाई गईं। इनमें से 588 इकाइयों को बैंकों ने वित्त पोषण कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा, जिनका बकाया ऋण 269 करोड़ रुपए था। कुल मिलाकर, 1,09,011 इकाइयां जिनका बकाया ऋण 4,757 करोड़ रुपए था, अर्थक्षम नहीं पाई गईं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण

3.27 खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को कंसर्टियम के नेता के रूप में रखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा बैंकों का एक कंसर्टियम बनाया गया। ये ऋण कंसर्टियम के पाँच बड़े बैंकों की औसत मूल उधार दर से 1.5 प्रतिशत कम पर दिए गए। अप्रैल 2007 के अंत में, योजना के अन्तर्गत बैंकों के कंसर्टियम द्वारा संवितरित किए गए 738 करोड़ रुपए में से लगभग 310 करोड़ रुपए बकाया थे।

फुटकर ऋण

3.28 यद्यपि बैंकों के फुटकर पोर्टफोलियो में वृद्धि 2005-06 के 40.9 प्रतिशत से घटकर 2006-07 के दौरान 29.9 प्रतिशत रह गई, यह बैंकिंग क्षेत्र के समग्र ऋण पोर्टफोलियो (28.5 प्रतिशत) की तुलना में अभी भी तेज गति से बढ़ी। परिणाम के रूप में, कुल ऋणों और अग्रिमों में उनका हिस्सा मार्च 2006 के अंत में 25.5 प्रतिशत से थोड़ा बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 25.8 प्रतिशत हो गया। फुटकर पोर्टफोलियो के अन्तर्गत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के ऋण में, पिछले वर्ष के विपरीत जब इसकी वृद्धि निम्नतम थी, 2006-07 के दौरान सर्वाधिक वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान क्रेडिट कार्ड की प्राप्तियों, ऑटो वाहन और अन्य वैयक्तिक ऋणों (मुख्यरूप से पेशेवरों को और शैक्षिक प्रयोजन के लिए दिये गये ऋणों) की वृद्धि में गिरावट आई। आवास ऋण, जो बैंकों के फुटकर पोर्टफोलियो के 46.0 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे बड़ा घटक था, भी घटा (सारणी III.7)।

3.29 यद्यपि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र (पूँजी बाजार, जमीन-जायदाद और पण्य) को दिए गए उधारों में पिछले वर्ष की उच्च वृद्धि से 2006-07 के दौरान तेजी से कमी आई, इसमें समग्र ऋण वृद्धि की तुलना में काफी अधिक दर से

सारणी III.7: बैंकों के खुदरा पोर्टफोलियो

(राशि करोड़ रु. में)

मद	मार्च के अंत में बकाया		घट-बढ़ प्रतिशत	
	2006	2007	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1. आवास ऋण	1,79,060	2,24,481	33.4	25.4
2. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	4,469	7,296	17.3	63.3
3. क्रेडिट कार्ड की प्राप्त राशियां	12,434	18,317	47.9	47.3
4. ऑटो ऋण	61,369	82,562	75.1	34.5
5. अन्य निजी ऋण	1,18,351	1,55,204	39.1	31.1
कुल खुदरा ऋण (1+2+3+4+5)	**3,75,683 (25.5)**	**4,87,860 (25.8)**	**40.9**	**29.9**
अनु. वाणिज्य बैंकों के कुल ऋण और अग्रिम	**14,73,723**	**18,93,775**	**31.0**	**28.5**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल ऋण और अग्रिमों में प्रतिशत अंश को दर्शाते हैं।
स्रोत : परोक्ष विवरणियां (घरेलू अ-लेखा परीक्षित और अनंतिम)।

सारणी III.8: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्र को ऋण

(मार्च के अंत में)

राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	2006		2007	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार	22,303 (40.6)	7.8	30,637 (37.4)	7.6
2. स्थावर संपदा बाजार	2,62,053 (80.0)	91.7	3,70,689 (41.5)	91.9
3. पण्य	1,413 (-40.3)	0.5	2,206 (56.1)	0.6
कुल (1+2+3)	**2,85,770 (74.4)**	**100.0**	**4,03,533 (41.2)**	**100.0**

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत अंतर दर्शाते हैं।

वृद्धि हुई। घटकों में, जबकि जमीन-जायदाद बाजार को दिए गए ऋण में तेजी से कमी आई, पण्यों को दिए गए ऋण में पिछले वर्ष की गिरावट के विपरीत तीव्रता से वृद्धि हुई (सारणी III.8)। संवेदनशील क्षेत्र के प्रति अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल एक्सपोज़र पिछले वर्ष के 18.8 प्रतिशत की तुलना में कुल बैंक ऋणों और अग्रिमों (जिसमें 18.7 प्रतिशत जमीन-जायदाद को, 1.5 प्रतिशत पूँजी बाजार को और 0.1 प्रतिशत पण्यों को शामिल है) का 20.4 प्रतिशत था।

3.30 बैंक समूहों के बीच, निजी क्षेत्र के नए बैंकों का संवेदनशील क्षेत्र के प्रति एक्सपोज़र (बैंकों के कुल ऋणों और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में मापित) मुख्य रूप से जमीन-जायदाद बाजार के प्रति अधिक एक्सपोज़र के कारण सर्वाधिक था, इसके पश्चात् विदेशी बैंक, निजी क्षेत्र के पुराने बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक थे (सारणी III.9 और परिशिष्ट सारणी III.11)।

निवेश

3.31 2006-07 के दौरान बैंकों के निवेश में 10.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जिसे मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से प्रोत्साहन मिला, इस प्रकार पिछले वर्ष का रुझान ही बदल गया जब 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् पहली बार सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश में समग्र रूप से कमी आई। निवेश पोर्टफोलियो के अन्तर्गत, गैर एसएलआर निवेश में एसएलआर पोर्टफोलियो की तुलना में अधिक वृद्धि दिखी। 2005-06 के दौरान 3.1 प्रतिशत (22,809 करोड़) की गिरावट की तुलना में 2006-07 के दौरान, सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के निवेश में 10.2 प्रतिशत (72,977 करोड़) की वृद्धि हुई। यद्यपि ऋण लेने की स्थिति सुदृढ़ बनी रही, मजबूत जमा वृद्धि ने निवेश के प्रति बैंकों की एक्सपोज़र क्षमता बढ़ाई।2006-07 के दौरान, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों में 74,238 करोड़ रुपए का वृद्धिशील निवेश किया। लेकिन, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों का कुल निवेश मार्च 2007 के अंत में (मार्च 2006 के अंत के 24.8 प्रतिशत की तुलना में) कुल आस्तियों का 21.8 प्रतिशत और एनडीटीएल का 28.0 प्रतिशत (पिछले वर्ष के एनडीटीएल के 31.3 प्रतिशत की तुलना में) था।

3.32 यद्यपि 2006-07 के दौरान 84,223 करोड़ रुपए का अधिक एसएलआर निवेश 25.0 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता के ऊपर था, कुछ बैंक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात पोर्टफोलियो को निर्धारित न्यूनतम स्तर के काफी करीब परिचालित कर रहे थे (चार्ट III.6)। 26 अक्तूबर 2007 को ऐसी प्रतिभूतियों की एनडीटीएल की 29.4 प्रतिशत की वाणिज्य बैंकों की धारिताएं मार्च 2007 के अंत के 28.0 प्रतिशत और एक वर्ष पहले के 28.8 प्रतिशत की तुलना में कुछ अधिक थीं । अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अधिक एसएलआर निवेश मार्च 2007 के अंत के 84,223 करोड़ रुपए

सारणी III.9 : संवेदनशील क्षेत्र को ऋण-बैंक समूहवार*

(प्रतिशत)

क्षेत्र	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		विदेशी बैंक	
	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूंजी बाजार #	1.2	1.3	2.3	2.2	1.3	1.5	2.6	2.4
स्थावर संपदा बाजार @	14.3	15.1	29.1	32.3	14.6	16.6	25.6	26.3
पण्य	0.1	0.1	–	–	0.2	0.5	–	–
संवेदनशील क्षेत्र को कुल अग्रिम	**15.6**	**16.6**	**31.4**	**34.5**	**16.0**	**18.7**	**28.2**	**28.7**

* : संबंधित बैंक समूह के कुल ऋण और अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में संवेदनशील क्षेत्र को दिए गए ऋण।
\# : पूंजी बाजार के जोखिम में निवेश तथा अग्रिम दोनों शामिल हैं ।
@ : स्थावर संपदा के जोखिम में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों उधार (लेने) शामिल हैं ।

सारणी III.10: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

(राशि करोड़ रुपए में)

क्षेत्र	31, मार्च 2006	कुल का प्रतिशत	30, मार्च 2007	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. वाणिज्यिक पत्र	4,821	5.4	8,978	9.4
2. शेयरों में निवेश	12,775	14.2	18,344	19.3
जिनमें से :				
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	2,274	2.5	2,126	2.2
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	10,501	11.7	16,218	17.1
3. बांडों/डिबेंचरों में निवेश	61,868	68.9	56,072	59.0
जिनमें से :				
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	32,345	36.0	28,472	30.0
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	29,523	32.9	27,600	29.0
4. म्युच्युअल फंड के यूनिट	10,345	11.5	11,659	12.3
कुल-गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश (1+2+3+4)				

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्य बैंको द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां ।

चार्ट III.6: एसएलआर प्रतिभूतियों में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवेश

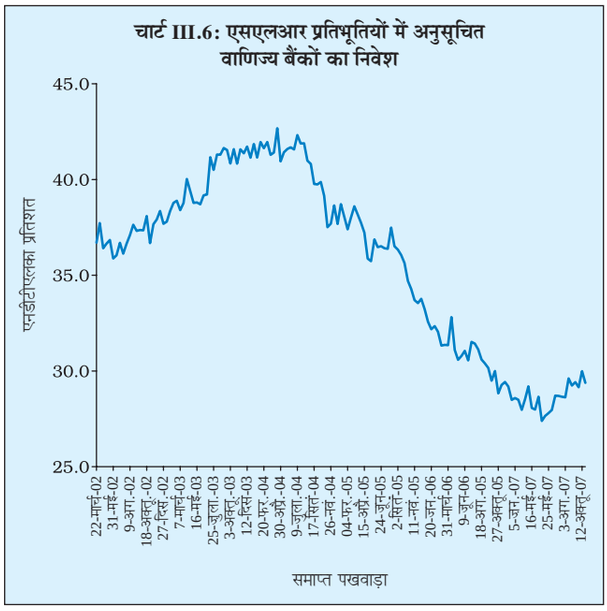

और एक वर्ष पहले के 1,00,626 करोड़ रुपए से बढ़कर 26 अक्तूबर 2007 को 1,41,437 करोड़ रुपए हो गए।

गैर एसएलआर निवेश

3.33 पिछले वर्ष में हुई 14.6 प्रतिशत (13,620 करोड़ रुपए) की गिरावट से तुलना करने पर 2006-07 में कंपनी क्षेत्र द्वारा जारी गैर एसएलआर प्रतिभूतियों (अर्थात, बांड/डिबेंचर/ शेयर और वाणिज्यिक पत्र) में बैंकों के निवेश 4.9 प्रतिशत (3,929 करोड़ रुपए) बढ़े, जिससे जमाराशिओं की सुदृढ़ वृद्धि परिलक्षित होती है। जबकि बांड/डिबेंचर में निवेश तेजी से कम हुए, शेयर और वाणिज्यिक पत्रों में बढ़े। कुल मिलाकर, मार्च 2007 के अंत में कुल गैर एसएलआर निवेश के प्रतिशत के रूप में कंपनी क्षेत्र के लिखतों (शेयर और बांड) में 53.5 प्रतिशत के निवेश पिछले वर्ष (55.9 प्रतिशत) की तुलना में कम थे। पिछले वर्ष के 28.3 प्रतिशत (3,40,573 करोड़ रुपए) से तुलना करने पर वाणिज्यिक क्षेत्र को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का कुल निधि प्रवाह, ऋण और गैर एसएलआर निवेश, 27.2 प्रतिशत (4,19,935 करोड़ रुपए) बढ़ा (सारणी III.10)।

3.34 लिखतों के अनुसार, यद्यपि मार्च 2007 के अंत में बांड और डिबेंचरों में निवेश तेजी से गिरा, वे अब भी गैर एसएलआर निवेश के सबसे बड़ा हिस्सा बने हुए थे (सारणी III.11)।

सारणी III.11: गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश की संरचना

(प्रतिशत)

लिखत	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक पत्र	7.2	3.1	2.7	2.7	5.4	9.4
बांड/डिबेंचर	81.7	84.2	81.5	79.2	68.9	59.0
शेयर	6.6	7.9	7.3	9.4	14.2	19.3
मुच्युअल फंड के यूनिट	4.5	4.9	8.5	8.7	11.5	12.3

स्रोत : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42(2) विवरणियां।

सारणी III.12: बैंकों की अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां-प्रकारानुसार

(मार्च के अंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

परिसंपत्ति	2005	2006	2007
1	2	3	4
अंतरराष्ट्रीय आस्तियां (1+2+3)	**1,33,237**	**1,58,201**	**2,02,973**
1. ऋण और जमाराशियां	1,24,582	1,46,014	1,90,888
	(93.5)	(92.3)	(94.0)
जिनमें से :			
क) अनिवासियों को ऋण *	4,103	6,270	7,122
	(3.1)	(4.0)	(3.5)
ख) निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण **	58,092	63,231	75,000
	(43.6)	(40.0)	(37.0)
ग) निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	26,171	31,556	40,846
	(19.6)	(19.9)	(20.1)
घ) *नोस्ट्रो* शेष @	35,673	44,515	67,487
	(26.8)	(28.1)	(33.2)
2. ऋण प्रतिभूतियों की धारिताएं	979	2,079	1,761
	(0.7)	(1.3)	(0.9)
3. अन्य आस्तियां @@	7,676	10,109	10,324
	(5.8)	(6.4)	(5.1)

* : अनिवासियों की जमाराशियों में से रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा ऋण को शामिल किया गया है ।
** : वि. मु. अनिवासी (बी) जमाराशियों से दिए गए ऋण और पीसीएफसी तथा एफसी को दिए गए उधार भारत के बैंकों में जमा राशियां ।
@ : विदेश के प्लेसमेंट एवं अनिवासी के बैंकों के पास शेष मीयादी जमाराशियाँ ।
@@ : भारतीय बैंकों की शाखाओं/सहायक संस्थाओं को आपूर्ति की गई पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ और अन्य अवर्गीकृत अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियां ।
टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।
स्रोत : स्थानगत बैंकिंग सांख्यिकीय।

बैंकिंग प्रणाली की अन्तरराष्ट्रीय आस्तियां

3.35 2006-07 के दौरान ऋण की सुदृढ़ मांग निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण तथा निवासियों द्वारा अनिवासियों पर जारी बकाया निर्यात बिल की अधिक वृद्धि में परिलक्षित हुई। 2005-06 के दौरान हुई 1.3 प्रतिशत की वृद्धि से तुलना करने पर कुल अन्तरराष्ट्रीय आस्तियों में नोस्ट्रो शेषों का हिस्सा 2006-07 के दौरान बढ़कर 5.1 प्रतिशत अंक हो गया (सारणी III.12)।

3.36 2005-06 के 24.9 प्रतिशत से तुलना करने पर आसन्न देशगत जोखिम के आधार पर, बैंकों के समेकित अन्तरराष्ट्रीय दावों में 2006-07 के दौरान 61.0 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि दिखी।समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों में अल्पकालिक दावों (एक वर्ष से कम शेष परिपक्वता) का हिस्सा 2006-07 के दौरान गिरना जारी रहा, जबकि दीर्घकालिक दावे तदनुसार बढ़े।

3.37 बैंकों के अन्तरराष्ट्रीय दावों का क्षेत्रवार स्वरूप व्यापक रूप से पिछले वर्ष के स्तर पर बना रहा। रिपोर्टिंग बैंकों का ऑफ़बैंक से इतर निजीट क्षेत्र के प्रति सर्वाधिक एक्सपोजर था, इसके पश्चात् बैंकिंग क्षेत्र था (सारणी III.13)।

3.38 वर्ष के दौरान, आसन्न देशगत जोखिम के आधार पर, बैंकों के देश-वार समेकित अन्तरराष्ट्रीय दावों में कुछ परिवर्तन हुआ। जहाँ कुल समेकित अन्तरराष्ट्रीय दावों में अमरीका और हांगकांग का हिस्सा काफी कम हुआ, वहीं लेकिन सिंगापुर का बढ़ा। ब्रिटेन, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा व्यापकरूप से पिछले वर्ष के स्तर पर रहा। अमरीका, ब्रिटेन, हांगकांग, सिंगापुर और जर्मनी पर कुल दावे कुल अन्तरराष्ट्रीय दावों के 53.9 प्रतिशत थे (सारणी III.14)।

तिमाही रुझान - वाणिज्य बैंकों का सर्वेक्षण[4]

3.39 2006-07 के दौरान अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की गतिविधियों के त्रैमासिक विश्लेषण से कुछ मनोरंजक बातें सामने आयी (सारणी III.15 और परिशिष्ट सारणी III.12)। चूँकि 2006-07 के दौरान सितंबर-अंत और मार्च-अंत के रिपोर्टिंग शुक्रवार 29 सितंबर 2006 और 30 मार्च 2007 को (क्रमशः छमाही और वार्षिक बंदी के समीप) पड़े, अन्य तिमाहियों तथा पिछले वर्ष की तदनुरूप तिमाहियों की तुलना में दूसरी और चौथी तिमाही में जमाओं तथा कुल ऋणों में तेज वृद्धि दिखी।

[4] बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 42(2) विवरणी के तहत प्राप्त सूचना पर आधारित।

सारणी III.13: बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावों का वर्गीकरण-परिपक्वता एवं क्षेत्रवार

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

अवशिष्ट परिपक्वता /क्षेत्र	2005	2006	2007
1	2	3	4
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय आस्तियां	**74,238**	**92,711**	**1,49,258**
(क) परिपक्वतावार			
1) अल्पावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष से कम)	61,113	73,176	1,09,481
	(82.3)	(78.9)	(73.4)
2) दीर्घावधि (अवशिष्ट परिपक्वता एक वर्ष तथा उससे अधिक)	11,951	18,627	39,775
	(16.1)	(20.1)	(26.6)
3) अनाबंटित	1,174	907	2
	(1.6)	(1.0)	(0.0)
(ख) क्षेत्रवार			
1) बैंक	34,301	43,050	69,781
	(46.2)	(46.4)	(46.8)
2) बैंकेतर पब्लिक	1,145	1,248	871
	(1.5)	(1.3)	(0.6)
3) बैंकेतर प्राइवेट	38,792	48,413	78,607
	(52.3)	(52.2)	(52.7)

टिप्पणियां: 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते है।

2. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में लागू नहीं परिपक्वता (अर्थात इक्विटी के लिए) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गई परिपक्वता सूचना शामिल है।
3. बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी मौद्रिक संस्थाएं (जैसे आइएफसी, ईसीबी आदि, और केंद्रीय बैंक शामिल हैं।
4. मार्च 2005 को समाप्त तिमाही से पूर्व बैंकेतर पब्लिक क्षेत्र में ऐसे बैंकों को छोड़कर जिनमें राज्य / केंद्रीय सरकारों की कम से कम 51 प्रतिशत शेयर धारिता थी, राज्य/केंद्र सरकार और उसके विभागों सहित कंपनियां/संस्थाएं शामिल थीं। मार्च 2005 की तिमाही से 'बैंकेतर पब्लिक' क्षेत्र में केवल राज्य / केंद्रीय सरकार और उनके विभाग शामिल हैं तथा तद्नुसार बैंकों को छोड़कर अन्य सभी संस्थाओं को '' बैंकेतर प्राइवेट'' क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा रहा है।

स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी पर आधारित - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

3.40 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान, मांग जमाओं में गिरावट के बावजूद, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में वृद्धि हुई। मांग जमाओं की गिरावट पिछली तिमाही के दौरान विशाल बढ़ोत्तरी की बिक्री, पारस्परिक निधियों पर चुकौती के दबाव और सार्वजनिक निर्गमों की संख्या में कमी में परिलक्षित हुई। तथापि, मीयादी जमाओं में तेज वृद्धि हुई जो ऋण की मांग को पूरा करने के लिए अधिक ब्याज दर और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा शुरू की गई जमा एकत्र करने की योजनाओं में परिलक्षित हुआ। बैंकों ने विदेशी मुद्रा आस्तियों को बेच दिया। इससे बैंक ऋण की मांग को पूरा कर पाए।

सारणी III.14: भारत से इतर देशों पर बैंकों के समेकित अंतरराष्ट्रीय दावे

(मार्च केअंत में)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	2005	2006	2007
1	2	3	4
कुल समेकित अंतरराष्ट्रीय दाव	**74,238**	**92,711**	**149,258**
जिनमें से :			
क) संयुक्त राष्ट्र अमरीका	22,348	23,176	32,875
	(30.1)	(25.0)	(22.0)
ख) यूनाइटेड किंगडम	7,608	14,212	22,598
	(10.2)	(15.3)	(15.1)
ग) हांगकांग	7,389	6,652	8,977
	(10.0)	(7.2)	(6.0)
घ) सिंगापुर	3,510	4,182	8,921
	(4.7)	(4.5)	(6.0)
ड) जर्मनी	3,607	4,678	7,234
	(4.9)	(5.0)	(4.8)
च) संयुक्त अरब अमीरात	2,771	4,059	6,686
	(3.7)	(4.4)	(4.5)

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े कुल अंतरराष्ट्रीय दावों प्रतिशत अंश हैं।
स्रोत : समेकित बैंकिंग सांख्यिकी - निकटवर्ती देश गत जोखिम आधार।

3.41 2006-07 की दूसरी तिमाही में, जमाओं और ऋण लेने से तेजी में वृद्धि हुई। जमाओं में अधिक वृद्धि मुख्य रूप से मीयादी जमाओं में वृद्धि के कारण थी, जो बढ़े हुए ब्याज दर को दर्शाती है। 1-3 वर्षीय परिपक्वता वाली मीयादी जमाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गईं ब्याज दरें मार्च 2006 की 5.75 - 6.75 प्रतिशत की सीमा से बढ़कर सितंबर 2006 में 6.25 - 7.50 प्रतिशत की सीमा में आ गईं। समान परिपक्वता वाली जमाओं पर निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गईं दरें 5.50 - 7.75 की सीमा से बढ़कर 6.75 - 8.25 प्रतिशत की सीमा में आ गईं। जमाओं में वृद्धि से अधिक ऋण वृद्धि हुई। जबकि बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को प्रतिबंधित कर दिया, उन्होंने विदेशी मुद्रा आस्तियों में अपने निवेशों को बढ़ाया।

सारणी III.15: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का परिचालन

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	मार्च 2007 के अंत में बकाया	घट-बढ									
		2005-06				2006-07				2007-08	
		ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2	ति.3	ति.4	ति.1	ति.2 अ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
घटक											
1. निवासियों की कुल जमाराशियां (क+ख)	25,41,201	7,145	1,29,596	13,065	1,90,983	30,677	1,66,396	31,469	2,62,886	62,265	1,99,683
क) मांग जमाराशियां	4,29,137	-22,249	41,167	-3,430	63,135	-41,272	43,300	-8,905	71,374	-41,305	52,052
ख)निवासियों की मीयादी जमाराशियां	21,12,063	29,394	88,430	16,495	1,27,848	71,949	1,23,096	40,374	1,91,511	1,03,569	1,47,630
2. वित्तीय संस्थाओं से मांग/ मीयादी निधीयन	85,836	-1,002	7,359	1,836	3,031	3,118	-1,576	-4,468	5,618	-2,984	5,609
स्रोत											
1. सरकार को ऋण	7,74,980	-1,457	18,324	-25,068	-11,314	23,238	10,723	602	39,675	51,145	62,155
2. वाणिज्य क्षेत्र को ऋण (क से घ)	20,87,511	12,862	1,04,416	53,032	1,72,011	22,606	1,41,465	64,777	1,95,164	-11,137	1,30,262
क. बैंक ऋण	19,28,913	8,994	1,15,035	62,858	1,67,981	14,050	1,40,364	74,213	1,93,208	-34,072	1,30,557
i. खाद्य ऋण	46,521	4,788	-5,255	1,464	-322	607	-7,840	8,171	4,891	-2,564	-6,948
ii. खाद्येतर ऋण	18,82,392	4,206	1,20,290	61,394	1,68,303	13,443	1,48,204	66,042	1,88,317	-31,507	1,37,505
ख. प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	2,799	7,130	-2,759	1,128	-2,913	-1,963	3,988	-2,783	-812	-282	780
ग. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	15,451	-532	-10	-736	-2,017	526	-1,132	-352	-304	-377	4,592
घ. अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1,40,347	-2,730	-7,851	-10,218	8,961	9,993	-1,756	-6,301	3,071	23,594	-5,667
3. वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (क+ख-ग)	-40,259	-2,057	-4,850	9,935	26,612	-21,137	10,844	13,322	2,327	2,465	-13,902
क. विदेशी मुद्रा आस्तियां	58,754	-2,179	-1,044	11,169	6,114	-13,919	8,830	11,781	8,567	-8,312	-8,568
ख. अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशियां	67,108	804	187	1,856	-19,723	3,917	1,671	1,233	1,011	-3,849	-2,110
ग. समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	31,905	-925	3,618	-622	-775	3,301	-3,685	-2,774	5,229	-6,928	7,443
4. निवल बैंक आरक्षित निधियां	1,90,086	3,060	9,679	-2,886	25,729	-6,090	20,381	-15,423	52,599	6,498	75,535
5. पूंजी खाता	2,02,618	20,359	2,530	9,342	8,090	12,025	6,168	2,250	4,447	26,996	20,985

अ : अनंतिम
* : 1 अप्रैल 2005 को घट बढ़।
टिप्पणी : 1. आंकड़े प्रत्येक तिमाही के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं।
2. मीयादी जमाराशियों में 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आईएमडी) का शोधन प्रभाव शामिल है।

3.42 2006-07 की तीसरी तिमाही में, कुल जमाओं और ऋण लेने में वृद्धि दूसरी तिमाही की तुलना में कम थी। लेकिन, वाणिज्यिक क्षेत्र को दिए गए ऋण कुल जमाओं में वृद्धि के दो गुने से अधिक थे। ऋण की बनी हुई मांग को पूरा करने के लिए, तिमाही के दौरान बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों और गैर -एस एल आर प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को बेच दिया। बैंकों ने तीसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा आस्तियों में अपने निवेशों को भी बढ़ाया।

3.43 2006-07 की चौथी तिमाही के दौरान कुल जमाराशियां और समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार दोनों तेजी से बढ़े जिससे बैंक बढ़ी हुई ऋण की मांग को पूरा कर सके। इसके अलावा, बैंकों ने सरकारी और गैर एसएसआर प्रतिभूतियों में भी अपने निवेशों को बढ़ाया। लेकिन, तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा आस्तियों में बैंकों के निवेश कम हुए।

3.44 2007-08 की पहली तिमाही में कुल जमाराशियां मामूली रूप से बढ़ी जबकि ऋण का देना ऋणात्मक हो गया। इसलिए, सरकारी और गैर एसएलआर प्रतिभूतियों दोनों में निवेश काफी बढ़ा।

3.45 2007-08 की दूसरी तिमाही के दौरान कुल जमा ओर ऋण देना दोनों तेजी से बढ़े। गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में बैंक के निवेश घटे, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश अधिक रहे। विदेशी मुद्रा

आस्तियों में बैंक के निवेश घटे जबकि तिमाही के दौरान उनके विदेशी उधार बढ़े।

ऋण-जमा अनुपात

3.46 2004-05 और 2005-06 में सुदृढ़ ऋण वृद्धि के परिणामस्वरूप ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात में कुछ असामान्य बात देखी गई। वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात, जो 11 जून 2004 तक वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात की तुलना में कम था, उसके बाद तेजी से बढ़ा, जबकि वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात में गिरावट आयी। 2005-06 में इस प्रवृत्ति में तेजी आयी क्योंकि सालभर ऋण जमा अनुपात निवेश-जमा अनुपात की तुलना में काफी अधिक बना रहा। निवेश-जमा अनुपात की तुलना में काफी अधिक होने की वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात की प्रवृत्ति पूरे 2006-07 के दौरान बनी रही। तथापि, ऋण वृद्धि में मामूली कमी और जमाओं में तेज वृद्धि को दर्शाते हुए, 2006-07 की दूसरी छमाही में वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात घटा। मार्च 2007 के अंत में, एक वर्ष पहले के 110 प्रतिशत से तुलना करने पर वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात लगभग 85 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) था। दूसरी तरफ, वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात, जो फरवरी 2007 के प्रारंभ तक 10 प्रतिशत से कम (कुछ पखवाड़ों में यह ऋणात्मक था) बना रहा, बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 14.6 प्रतिशत और अगस्त 2007 के प्रारंभ तक 17.7 प्रतिशत हो गया। परिणाम के रूप में, दोनों अनुपातों के बीच का अंतर कम हुआ। पिछले वर्ष की तरह, वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात और निवेश-जमा अनुपात के बीच सामान्यतया ऋणात्मक संबंध दिखे (चार्ट III.7)।

3.47 बकाया राशि के आधार पर, ऋण-जमा और निवेश-जमा अनुपात 1999 और 2004-05 की तीसरी तिमाही के बीच न्यूनाधिक रूप से उसी दिशा में रहा परंतु इसके पश्चात उनमें विपरीत दिशाओं में बढ़ने की प्रवृत्ति रही । यह स्वरूप 2006-07 में और आगे बढ़ा क्योंकि ऋण-जमा अनुपात और बढ़कर मार्च 2007 के अंत में 74.0 प्रतिशत के सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुँच गया, जबकि निवेश-जमा अनुपात गिरकर 30.3 प्रतिशत नीचे तक पहुँच गया (चार्ट III.8)।

3.48 बैंक समूहों के बीच , विदेशी बैंकों का ऋण -जमा अनुपात (बकाया राशि के अर्थ में) मार्च 2007 के अंत में सर्वाधिक था, इसके पश्चात निजी क्षेत्र के नए बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के पुराने बैंक थे (चार्ट III.9)।

3.49 अलग-अलग बैंकों के स्तर पर, मार्च 2007 के अंत के ऋण-जमा अनुपात में व्यापक अंतर दिखे, विशेष रूप से विदेशी बैंकों में। आइडीबीआइ लि. को छोड़कर, जिसका ऋण-जमा अनुपात 144.1 प्रतिशत था, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 59.6 प्रतिशत (यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) और 80.0 प्रतिशत (स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर) के बीच था। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में, ऋण-जमा अनुपात 52.7 प्रतिशत (बैंक ऑफ राजस्थान) और 77.7 प्रतिशत (आइएनजी वैश्य बैंक) (सांगली बैंक को छोड़कर जिसका आइसीआइसीआइ के साथ समामेलन किया गया) के बीच था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 60.2 प्रतिशत (डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक) और 99.3 प्रतिशत (कोटक महिंद्रा बैंक) के बीच था। विदेशी बैंकों के मामले में, ऋण-जमा

चार्ट III.7: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का ऋण-जमा एवं निवेश-जमा अनुपात

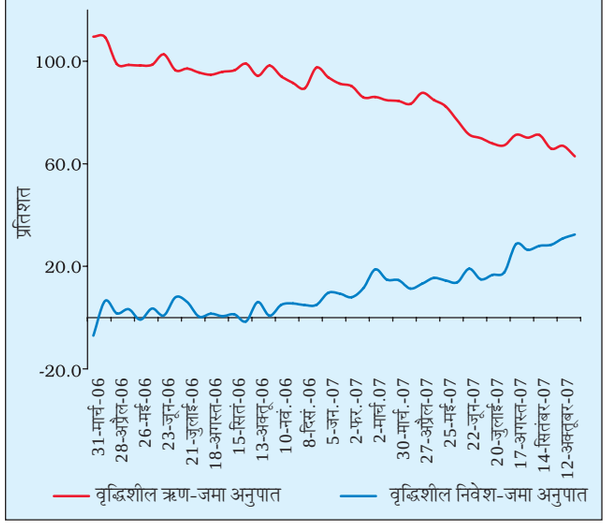

चार्ट III.8: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सी-डी और आइ-डी अनुपात
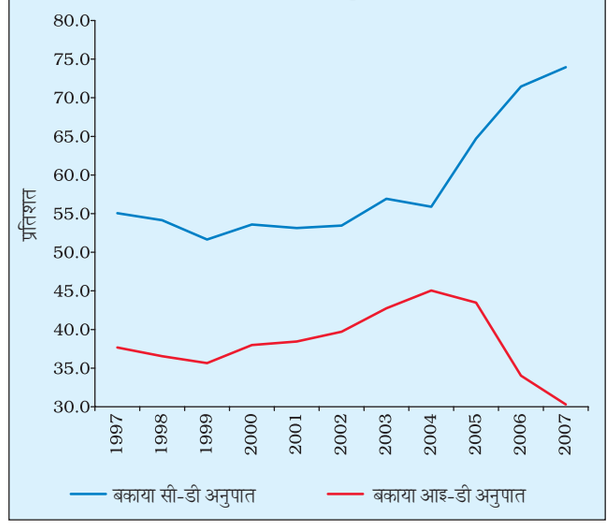
(मार्च के अंत में अनुसार)